

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] दिल्ली, बुध्स्पतिवार, फरवरी 27, 2014/फाल्गुन 8, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 248  
No. 30] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2014/PHALGUNA 8, 1935 [N.C.T.D. No. 248

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

सं. एफ. 9(17)/अ.एवं सा./वा.औ.स./2013/3537.— सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठनीय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 3 और 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची-I में उल्लिखित विवरण के अनुसार, विनिर्माण और इससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में सांख्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़ों के संग्रहण, अब से “वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2012-13(राज्य प्रतिदर्श)” के रूप में संदर्भित, का निर्देश देता है।

2. आगे, उपराज्यपाल, श्री रवि कांत शर्मा सहायक निदेशक ( औ. सां. ), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को, उपरोक्त निर्देश के संदर्भ में वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2012-13 (राज्य प्रतिदर्श) के लिए सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा प्रदत्त सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकार्डों के निरीक्षण और जैसा भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण मांगने के कार्य में लगाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र अथवा प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा।

4. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2012-13 के संबंध में भाग-I तथा भाग-II में सूचना प्रदाता द्वारा प्रदत्त किए गए आंकड़ों को विधिवत् सत्यापन और जांच के बाद अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा।

5. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2012-13 से संबंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे।

**अनुसूची**

1. **सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन:**—वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2012-13 के माध्यम से, विनिर्माण, प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, गैस और जलापूर्ति तथा शीत भंडार से संबंधित कार्यकलापों वाले संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, संरचना और ढांचे से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण किया जाता है।

2. **सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र:**—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2012-13, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित किया जाता है।

3. **आंकड़ा संग्रहण की पद्धति:**—प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के तहत सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उस तारीख, जब तक, अधिकारी अथवा कार्यालय जिसे, इकाई (यूनिट) और इकाइयों (यूनिट्स) जिनके लिए और फॉर्मेट जिसमें सूचना प्रदान की जानी है, का उल्लेख करेगा। सांख्यिकी अधिकारी सूचनादाताओं को, उन अन्य शर्तों पर निर्भर करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निर्धारित सूचना फाइल करने की अनुमति दे सकता है, जिन्हें वह नोटिस में विनिर्दिष्ट करेगा।

4. **सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं:**—इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी [यानि, कोई फैक्ट्री अथवा कोई विद्युत या गैस या जलापूर्ति प्रतिष्ठान अथवा बीड़ी और सिगार कामगार (नियोजन की शर्तों) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत कोई उद्यम], जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है, इकाई के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा।

5. **यदि अलग-अलग इकाइयों के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है तो, सांख्यिकी अधिकारी मालिक अथवा पदाधिकारी को एक ही प्रबंध के तहत दो या अधिक इकाइयों के संबंध में उन शर्तों पर निर्भर करते हुए समेकित सूचना प्रदान करने के लिए कह सकता है, जिन्हें उसने नोटिस में विनिर्दिष्ट किया है।**

6. **सांख्यिकी संग्रहण का कार्य पूरा करने की अवधि:**—नोटिस में प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा और आमतौर पर यह अवधि दिसम्बर, 2013 से जून, 2014 के बीच होनी चाहिए।

7. **संदर्भ अवधि:**—सूचना, 1 अप्रैल, 2012 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई के मामले में 1 अप्रैल, 2012 और 31 मार्च, 2013 के बीच किसी भी तारीख को पड़ने वाले लेखाकरण वर्ष के लिए उपलब्ध करानी होगी।

8. **एकत्र की जाने वाली सूचना का स्वरूप:**—अपेक्षित सूचना के दो भाग हैं, भाग-I परिसंपत्तियों तथा देयताओं, रोजगार और श्रम लागत, प्राप्तियों, व्यय, निर्देश की स्वदेशी तथा आयातित वस्तुओं, उत्पाद तथा उप-उत्पाद, वितरण संबंधी खर्च आदि से संबंधित है। भाग-II श्रम सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं नामतः, कार्य दिवस, नियोजित श्रम दिवस, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, नियोजित कार्य के घंटों, आय तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में सूचना से संबंधित है।

9. **सूचनादाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना की भाषा:**—सूचनादाता, निर्धारित प्रपत्र में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सूचना प्रदान करेगा।

10. **सूचनादाता की बाध्यता:**—इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी, संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से उसे प्राप्त नोटिस में उल्लिखित तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा। सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, वह निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड भी उपलब्ध कराएगा और मांगी गई सूचना के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देगा।

11. **उन कारोबारी रिकार्ड तथा अन्य रिकार्डों का स्वरूप, जिनका निरीक्षण किया जा सकता है:**—सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में बैलेंस शीट, लाभ तथा हानि खाता, मस्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रमिक रजिस्टर, पे-रोल, निर्देशक की रिपोर्ट अथवा अन्य कानूनी दस्तावेज जैसे कारोबारी रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है।

12. **निरीक्षण का तरीका:**—संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबारी रिकार्ड और अन्य रिकार्डों के आधार पर इकाई द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन कर सकता है और इकाई के मालिक अथवा पदाधिकारी अथवा प्रबंधमंडल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के  
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
डॉ. एम. एम. कुट्टी, प्रधान सचिव (योजना)

**DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS****NOTIFICATION**

Delhi, the 27th February, 2014

No. F. 9(17)/DES/ASI/2013/3537.—In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs collection of statistics on manufacturing

and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as "the Annual Survey of Industries 2012-13 (state samples)" as per the details mentioned in the Schedule given below.

2. The Hon'ble Lieutenant Governor further appoints Sh. Ravi Kant Sharma, Assistant Director (ASI), Directorate of Economics and Statistics, National Capital Territory of Delhi as Statistics Officer for the Annual Survey of Industries 2012-13 (state samples) with reference to the aforesaid direction.

3. The persons authorized by the concerned Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer.

4. The statistics collected in Part-I and Part-II in respect of the Annual Survey of Industries 2012-13 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Directorate of Economics and Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi.

5. All the persons engaged in any activity in respect of Annual Survey of Industries 2012-13 (state samples) are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011.

#### SCHEDULE

1. **Subject and purpose for collection of Statistics:**—Statistics relating to the growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries 2012-13.

2. **Geographical area for collection of Statistics:**—The Annual Survey of Industries 2012-13 will be conducted in the whole of National Capital Territory of Delhi, under the Collection of Statistics Act, 2008.

3. **Method of data collection:**—A notice will be issued by Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. A Statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.

4. **Nature of informants from whom data may be collected:**—The owner or occupier of a unit [i.e., a factory or an electricity or gas or water supply undertaking or an establishment registered under the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966], who would be issued notice by a Statistics Officer, shall furnish information about the unit.

5. The Statistics Officer may require an owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more units under single management in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.

6. **Period during which collection of Statistics may be completed:**—The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall during December, 2013 to June, 2014.

7. **Reference Period :-** Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1<sup>st</sup> April, 2012 and ending on 31<sup>st</sup> March, 2013 or for the accounting year of a unit ending on any date between 1<sup>st</sup> April, 2012 and on 31<sup>st</sup> March, 2013.

8. **Nature of information to be collected:**—The information required has two parts. Part-I relates to information on assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items – indigenous and imported, products and by-products, distributive expenses etc. Part-II relates to information on different aspects of labour statistics, namely, working days, mandays worked, absenteeism, labour turnover, man-hours worked, earning and social security benefits.

9. **Language in which information is to be furnished by informant:**—Every informant shall furnish information in the prescribed format either in Hindi or in English.

10. **Obligation of informant:**—The owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

11. **Nature of business records and other records which may be inspected:**—Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

12. **The manner of inspection:-** The concerned Statistics Officer or any person authorized by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

By Order and in the Name of Lt. Governor,  
of the National Capital Territory of Delhi,  
Dr. M. M. KUTTY, Pr. Secretary (Plg.)

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

संख्या एफ/डी.ई.15(1031) अधिनियम/2014/21626-37.— दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के नियम 43 सहपठित दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 की धारा 3 को उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निजी मान्यताप्राप्त विद्यालय (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) आदेश, 2007, यथा संशोधित, में निम्न संशोधन करते हैं :-

**1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**

(1) इन नियमों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) (संशोधन) आदेश, 2014 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

2. निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) आदेश, 2007, के -

"(क) उप-खण्ड 14(ख) में, उप-खण्ड (iv) के नीचे दी गई तालिका में -

(i) पंक्ति संख्या 4 व प्रविष्टियां जो कॉलम संख्या 1, 2 एवं 3 के विपरीत दर्शाई गई हैं, को हटाया जाता है।

(ii) कॉलम संख्या 3 में, कुल योग के विपरीत दर्शाई गई संख्या "100" के स्थान पर संख्या "95" को प्रतिस्थापित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. मधु रानी तेवतिया, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

**DIRECTORATE OF EDUCATION**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 27th February, 2014

No.F/BE/15/1031/ACT/2014/21626-37.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) read with rule 43 of the Delhi School Education Rules, 1973 the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following order to further amend the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-Primary classes) Order, 2007 as amended up to date, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-Primary classes) (Amendment) Order, 2014.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-Primary classes) Order, 2007,—

(a) In clause 14 (b), in the Table below sub- clause (iv),—

(i) The row at S. No. 4 and entries relating thereto in columns no. 1, 2 and 3, shall be omitted;

(ii) In column no. 3, for the number "100", appearing against the entry "Total", the number "95" shall be substituted."

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
Dr. MADHU RANI TEOTIA, IAS, Addl. Secy. (Education)

## उद्योग विभाग

## अधिसूचना

दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

सं. एफ.1/जे.सी.आई./सी.ई.टी.पी./मीटिंग/2009/30/232.—जबकि दिनांक 28 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या फा. नं. एफ.1/जे.सी.आई./सी.ई.टी.पी./मीटिंग/2009/38 के अनुसार उद्योग आयुक्त, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली सामूहिक अवजल शोधन संयंत्र अधिनियम, 2000 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अन्तर्गत किसी अधिभोगी से किसी बकाये की वसूली के प्रयोजनार्थ और उक्त प्रयोजन के लिए नोटिस जारी करने के लिए संलग्न प्रथम अनुसूची में उल्लेखित सार्वजनिक मलशोधन संयंत्र समितियों को शक्तियाँ सौंपी थी।

अतः अब उद्योग आयुक्त, दिल्ली सामूहिक अवजल शोधन संयंत्र अधिनियम, 2000 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना से संलग्न प्रथम अनुसूची में सम्बन्ध सार्वजनिक मलशोधक संयंत्र समितियों में आंशिक संशोधनों के साथ क्रम संख्या 10 और 11 पर वजीरपुर सार्वजनिक मलशोधन समिति एवं नारायण सार्वजनिक मलशोधक समिति के नाम भी इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से सम्मिलित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से तथा उनके नाम पर,

अमित यादव, सचिव एवं आयुक्त (उद्योग)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES  
NOTIFICATION

Delhi, the 27th February, 2014

No. F. 1/JCI/CETP/Meeting/2009/30/232.—Whereas vide Notification No. F. 1/JCI/CETP/Meeting/2009/38 dated the 28<sup>th</sup> January, 2010, the Commissioner of Industries, Government of National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred under section 15 of the Delhi Common Effluent Treatment Plan Act, 2000, delegated the powers under clause (b) of sub-section (2) of Section 6 read with Section 16 of the said Act to the respective CETP Societies for the respective industrial areas under their control as per Schedule 1 annexed therewith for the purpose of recovery of any dues from any occupier in the manner laid down in the said Act and to issue notices for the said purpose.

Whereas, in partial modification of Schedule 1 annexed to the said notification containing the list of CETP Societies, and in exercise of the Powers of Section 15 of the said Act, the Commissioner of Industries adds the names of Wazirpur CETP and Naraina CETP at serial number 10 and 11 respectively with effect from the date of publication of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,  
AMIT YADAV, Secy. & Commissioner (Industries)

कार्यालय: अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक

## अधिसूचना

दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

सं. फा. 07(7)/2013-14/डीएससीएसटी/एससीपी/खण्ड-VIII/21152.—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की उप-धारा (2) धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 06-12-2016 की तिथि निर्धारित करते हैं, जिस तिथि तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्थानीय प्राधिकरण जैसे उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर परिषद् को, अपने अधिकार क्षेत्र में, खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने हेतु, प्रयोज्य संख्या में स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर,

डी.एस.पंडित, सचिव (अनु.जा/अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसं.)

658 09/14-2

**DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES****NOTIFICATION**

Delhi, the 27th February, 2014

**No. F.7(7)/2013-14/DSCST/SCP/Vol.VIII/21152.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby specifies 6 December, 2016 as the date by which the Local Authorities in National Capital Territory of Delhi, i.e. North Delhi Municipal Corporation, South Delhi Municipal Corporation, East Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Council, within their jurisdiction, have to construct adequate number of sanitary community latrines to eliminate the practice of open defecation.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,  
D.S. PANDIT, Secy.(SC/ST/OBC/MIN.)